Alleged delay in sanction of out turn Telephone Connections

1159. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that after authorisin the CGM of State capitals to sanction out of turn telephone connections the whole process takes loger time as compared to the earlier system; and

(b) if so, what steps Government propose to take to remedy the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir. Majority of the telephones recommended by Hon'ble MPs are installed within a period of 30 days. However, in a few cases due to technical non-feasibility, and delayed receipt of registration particulars from the parties etc., installation of telephone connection takes some what longer time.

(b) Does not arise.

उप महानिदेशक (एस०आर०) के विरूद्ध शिकायतें

1160. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सांसदों से कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उप-महानिदेशक (एस०आर०) के कार्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करवाने की मांग की गई है ;

(ख) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सांसदों द्वारा उन्हें लिखे गए ऐसे पत्रों की संख्या इस समय कितनी है, जिनका उप-महानिदेशक (एस०आर०) द्वारा अंतिम रूप से उत्तर नहीं दिया गया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) माननीय संसद सदस्यों से एक कर्मचारी को क्वार्टर अलाट करने के बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं जिसे वे समझते हैं कि उन्हें क्वार्टर अलाट करने के मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई। मामले की जांच करवाई गई और पता चला कि प्रश्नगत मामले में नियामनुसार सख्ती से कार्रवाई की गई और सांसदों के पत्रों के विधिवत् उत्तर दिए गए।

(ग) सांसदों के पत्रों का उत्तर मंत्री स्तर पर दिया जाता है। पिछले 6 महीनों के दौरान सांसदों से प्राप्त उन पत्रों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है जिनका संबंध उप-महानिदेशक (एस०आर०) से था :—

(i)	प्राप्त पत्रों की संख्या :	123
(ii)	उन पत्रों की संख्या जिनके अंतिम उत्तर दिए गए :	70
(iii)	जिन पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है उनकी संख्या	53

संचार मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार

1161. **श्री राजू भाई ए० परमार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों/संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और उनमें से कितने अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है;

(ग) भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 45 अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए विभिन्न आरोपों की जांच के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संदिग्ध सत्यनिष्ठा के आरोप के कारण एक अधिकारी को नौकरी से हटा दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर निरंतर निवारक और दंडात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जहां आवश्यक होता है, गंभीर प्रकृति के मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता ली जाती है और ऐसी जांच पड़ताल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध जांच

1162. **श्री राजूभाई ए० परमार :**
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
श्री पर्वतलेनि उपेन्द्र :
श्री एन०ई० बलराम :
श्री रामदास अग्रवाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध एक मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) निष्पक्ष रूप से जांच कराने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) हाल ही में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा किए गए कुछ मुख्य सौदों (खरीददारी सहित) की जांच की गई है। इस जांच के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को औपचारिक जांच के लिए एक विशेष मामला सौंपा गया है। विभाग ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जो सेवा-निवृत्त हो गए हैं, को कारण बताओ नोटिस भी दिया है।

Instruction for stopping new sanctions/institution of Telephone Connections

1163. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have issued instructions for stopping of new sanctions/installations of telephone connections in Delhi; and

(b) if so, what are the reasons which led to this position?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS SHRI (P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Amendments in the Cable T.V. Legislation

@1164. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Law Ministry has approved the amendments sought by the Department of Telecommunications and Information and Broadcasting Ministry, in the proposed Cable TV legislation as reported in the Economic Times dated the 1st June, 1992;

@Previously Unstarred Question 821, transferred from 16th July, 1992.